जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 | वर्षः 51 | संख्याः 185 | प्रभात | कोटा, सोमवार 20 अप्रैल, 2026 | कोटा/24/2012-14 | पृष्ठ 6 | मूल्य 2.50 रु.

बंगाल में भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मुख्य मुद्दा बनाया

भाजपा नेताओं ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन्स नैक) की सुरक्षा को मजबूती से उठाया

■ प्रधानमंत्री ने सिलीगुड़ी की एक जनसभा में तृणमूल कांग्रेस पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत से अलग करने की धमकी देने वालों का समर्थन करने का आरोप लगाया।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अप्रेल। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित, सभी शीर्ष भाजपा नेताओं के भाषणों में एक साझा विषय राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ और राज्य के उत्तर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे "चिकन्स नैक" भी कहा जाता है, रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह संदेश स्थानीय लोगों के बीच भी प्रभावी रहा है, जिनके लिए बांग्लादेश से घुसपैठ एक बढ़ता हुआ मुद्दा बन रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सिलीगुड़ी की रैली में अपने भाषण में कहा, हमारा सिलीगुड़ी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वारों में से एक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर मातृभूमि भारत के लिए अति आवश्यक है। मैं आपको तृणमूल कांग्रेस की गलतियों का उदाहरण देना चाहता हूं, जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है। देश में एक टुकड़े-टुकड़े गैंग है। इस गैंग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर से संबंधित धमकी दी थी। उन्होंने उत्तर-पूर्व को देश से अलग करने की बात की है। अपनी तुष्टिकरण नीति को आगे बढ़ाने के लिए, तृणमूल कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन सड़कों और संसद में करती है।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, भाजपा के लिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर राष्ट्रीय सुरक्षा और समृद्धि का मार्ग है। और हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस जगह को मजबूत बनाया जाए। सेवोक-रंगपो रेलवे लिंक इसका एक उदाहरण है। इस परियोजना से सिक्किम सिलीगुड़ी और देश के रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। इस पर कार्य तेजी से प्रगति पर है। यह परियोजना कनेक्टिविटी को सुधारने और व्यापार और पर्यटन को बढ़ाने में मदद करेगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक घुसपैठ के संदर्भ में एक संवेदनशील क्षेत्र है। क्षेत्र के स्थानीय लोग बांग्लादेश से घुसपैठ की शिकायत करते हैं। यह कहते हुए कि घुसपैठ करने वाले पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के संसाधनों पर दबाव डालते हैं, जो कई अंतरराष्ट्रीय नदियों का घर है। यह रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए, सरकार इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है।

भाजपा का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए भूमि सौंपने में देरी की है।

पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सदस्य हर्षवर्धन श्रिंगला ने कहा, "सिलीगुड़ी कॉरिडोर वह भूमि खंड है, जो हमारे देश के उत्तर-पूर्व को भारत के शेष हिस्से से जोड़ता है। यह 22 किलोमीटर की बहुत संकरी पट्टी है। दार्जलिंग निर्वाचन क्षेत्र दुनिया का शायद एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें तीन अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ हैं। यह पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश से जुड़ा है। अगर आप थोड़ा उत्तर की ओर जाएं, तो आप चीन की सीमा तक भी पहुँच जायेंगे। इस प्रकार यह हमारे देश का बहुत संवेदनशील हिस्सा है, और यहां सुरक्षा-संबंधी महत्वपूर्ण चिंताएं हैं, जो रणनीतिक स्थिति के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। घुसपैठ और अन्य सुरक्षा-संबंधी मुद्दे चुनावी नैरेटिव में भी अहम भूमिका निभाते हैं।"

ईरान ने वार्ता के लिए पाकिस्तान जाने से मना किया

■ ट्रंप ने कहा कि सोमवार को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद जाएगा।

तेहरान/वॉशिंगटन, 19 अप्रैल। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की शांति वार्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जहां एक और ट्रंप ने ईरान को डील करने के लिए आखिरी धमकी दे डाली है, तो वही नाकाबंदी से खफा ईरान वार्ता से पीछे हटने की धमकी दे रहा है। बता दें कि दूसरे दौर की भी वार्ता इस्लामाबाद में होनी है, लेकिन वार्ता से पहले कई पेच फंस गए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य के पास जहाजों पर गोलीबारी करके ईरान ने दोनों देशों के बीच हुए युद्धविराम का पूर्ण उल्लंघन किया है। लेकिन उन्होंने कहा, इसके बावजूद इस्लामाबाद में मंगलवार को होने वाली शांति वार्ता के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सोमवार को रवाना होगा। उन्होंने धमकी दी कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इस बार सबसे कठिन चुनावी मुकाबले का सामना कर रही हैं ममता बनर्जी

सत्ता विरोधी लहर के साथ भारी भ्रष्टाचार के आरोप और भाजपा की ताकत ने उनके लिए भारी चुनौतियां पैदा कर दी हैं

■ लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ममता का अब तक का राजनैतिक सफर दर्शाता है कि जब वे मुश्किल मुकाबले में होती हैं तो बेहद साहसी और आक्रामक हो जाती हैं।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अप्रेल। बंगाल उच्च-स्तरीय चुनाव के लिये तैयार हो रहा है, वहीं, बहुत से लोगों का मानना है कि इस बार ममता बनर्जी को कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस की संस्थापिका 71 वर्षीय ममता बनर्जी तीन कार्यकाल से मुख्यमंत्री हैं।

उनकी पार्टी को एंटी-इंकम्बेंसी (सत्ता-विरोध) और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा सत्ता परिवर्तन की हर संभव कोशिश कर रही है और विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) ने अनिश्चितता और भ्रम को और बढ़ा दिया है। लेकिन ममता का राजनीतिक सफर यह दर्शाता है कि जब उन्हें कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ता है, तो वे बहुत ज़्यादा साहसी और आक्रामक होती हैं।

बनर्जी जब 17 साल की थीं, तब उनके पिता, प्रोमिलेश्वर बनर्जी, का निधन हो गया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिता का निधन इलाज की कमी के कारण हुआ और परिवार मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं कर सका, क्योंकि सरकारी विभाग उनके पिता, जो एक ठेकेदार थे, के बकाया भुगतान को मंजूरी नहीं दे रहे थे। उनके पिता की मृत्यु के अगले दिन हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित बनर्जी के घर एक चेक के रूप में 60,000 रुपये पहुँचे। उन्होंने 2012 में "आउटलुक" को दिये इस इन्टरव्यू में बताया, "चेक बेकार था; यह मेरे पिता को वापस नहीं ला सकता था। केवल भगवान ही हमारे दर्द और बाबा के जाने के बाद के हमारे संघर्ष का साक्षी है।"

कॉलेज छात्रा के रूप में, बनर्जी का जीवन अपने साथियों से अलग था। वे सुबह-सवेरे उठकर अपने पाँच भाई-बहनों और मां के लिए खाना बनाती थीं,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हम युद्ध नहीं चाहते, आत्मरक्षा में कदम उठा रहे हैं- ईरानी राष्ट्रपति

उन्होंने कहा कि ट्रंप ईरान को न्यूक्लियर अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते

■ राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इज़रायल ने ईरान के नागरिक ढाँचों को निशाना बनाया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा मानवाधिकार का उल्लंघन है।

तेहरान, 19 अप्रैल। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने स्पष्ट किया है कि उनका देश किसी भी तरह के युद्ध का पक्षधर नहीं है और मौजूदा हालात में केवल आत्मरक्षा के तहत कदम उठा रहा है। ईरानी स्टूडेंट न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया है और न ही उसका ऐसा कोई इरादा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना तेहरान की प्राथमिकता है।

राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने अमेरिका और इज़रायल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों देशों ने नागरिक ढांचों को निशाना बनाया है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने इसे मानवाधिकारों पर दोहरे मापदंड का उदाहरण बताया। पेजेश्कियन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की, उन्होंने कहा कि ट्रंप के पास ईरान को उसके परमाणु अधिकारों से वंचित करने का कोई ठोस कारण नहीं है।

उन्होंने कहा, 'ट्रंप कहते हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वे यह नहीं बताते कि किस जुर्म के लिए। वे कौन होते हैं किसी देश को उसके अधिकारों से वंचित करने वाले?

रिपोर्ट के मुताबिक, वाशिंगटन और तेहरान के बीच परमाणु मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। इसी बीच ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने अपने रुख को दोहराते हुए कहा है कि देश अंतरराष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहकर अपने अधिकारों की रक्षा करेगा।

वहीं ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बघेर कालिबाफ ने भी कहा कि उनका देश स्थायी शांति चाहता है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका पर अविश्वास जताते हुए कहा कि ईरान की नीयत स्पष्ट है और वह ऐसी स्थिति चाहता है, जहां भविष्य में युद्ध की आशंका न रहे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका पर भरोसे की कमी है, लेकिन हम स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि इस्लामाबाद में पहले दौर की वार्ता के वक्त भी ऐसा ही हुआ था और ईरान ने कहा था कि उसे अमेरिका की बातों पर विश्वास नहीं है।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी बाँग्लादेश में उच्चायुक्त बने

■ वे लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे, फिर भाजपा में शामिल हो गए। उनके पास प्रशासन व राजनीति का लंबा अनुभव है।

नई दिल्ली, 19 अप्रैल। भारत सरकार ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को भारत-बांग्लादेश संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

दिनेश त्रिवेदी एक वरिष्ठ राजनेता हैं, जो केन्द्र सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं। वे लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस से जुड़े रहे और बाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए। उनके पास प्रशासन और राजनीति का लंबा अनुभव है, जिसे इस नई भूमिका में उपयोगी माना जा रहा है।

बांग्लादेश भारत का एक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका बंदरगाहों की घेराबंदी खत्म करे, तब होर्मुज़ खुलेगा- ईरान

दूसरी ओर ट्रंप ने कहा कि जब तक समझौता नहीं हो जाता, नौसैनिक घेराबंदी जारी रहेगी

■ ईरान का कहना है कि लेबनान में संघर्ष विराम के बाद होर्मुज़ से सुरक्षित आवाजाही की घोषणा की थी, पर अमेरिका ने यह कह कर बाधा डाली कि मार्ग तो खुला है, पर ईरानियों के लिए नहीं। यह बात हमें चुभ गई।

तेहरान/वाशिंगटन/बेरूत, 19 अप्रैल। होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर गहराया संकट निकट भविष्य में हल होता नहीं दिख रहा। दुनिया ईरान और अमेरिका से जल्द ही इस मसले को सुलझाने की अपील करते-करते हार चुकी है। दूसरे दौर की बातचीत के करीब आते, दोनों देशों के बीच अविश्वास और मतभेदों का दायरा और बढ़ गया है। ईरान ने काफी हद तक अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ईरान ने बिना लाग लपेट के कहा कि वह होर्मुज़ स्ट्रेट को तभी खोलेगा, जब अमेरिका की सेना उसके बंदरगाहों की घेराबंदी खत्म कर लौट जाएगी।

अल जजीरा और सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के उप विदेशमंत्री सईद खतीबजादेह ने कहा कि अमेरिका के साथ आमने-सामने की बातचीत के नए दौर के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। उन्होंने हठधर्मिता के लिए वाशिंगटन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने साफ किया कि अगर अमेरिका चाहता है कि होर्मुज़ स्ट्रेट खुले तो उसे सबसे पहले हमारे बंदरगाहों की घेराबंदी खत्मकर सेना को लौटने का आदेश देना होगा।

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक समझौता नहीं होगा, तब तक ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक घेराबंदी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन तेहरान के किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगा। खतीबजादेह ने तुर्किये के अंताल्या डिप्लोमेसी फोरम में पत्रकारों से कहा है कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच अगले दौर की बातचीत के लिए कोई भी तारीख तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा, अभी तक हम आपसी समझ का ढांचा तय करने पर ध्यान दे रहे हैं। इस पर सफलता मिलने पर अगले कदमों की घोषणा होगी। अगर अमेरिका अतिवादी रवैया न अपनाता तो समझौता काफी पहले हो जाता।

उन्होंने कहा, ईरान अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में ही अमेरिका से कोई समझौता करेगा। परमाणु अप्रसार संधि और अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी सदस्य होने के नाते ईरान की कुछ जिम्मेदारियां हैं और कुछ अधिकार भी हैं। ईरान अपने अधिकारों का हकदार है। लेबनान में संघर्ष विराम के बाद हमने कहा कि होर्मुज से अब सुरक्षित आवाजाही होगी। मगर इसमें अमेरिका ने बाधा डाल दी।

उसने कहा दिया यह मार्ग खुला तो है, लेकिन ईरानियों के लिए नहीं। यही बात हमें चुभ गई। और दुर्भाग्य से वह अभी भी बातचीत के जरिए कूटनीतिक तमाशे की कोशिश कर रहा है।

ईरानी संसद के अध्यक्ष ने शनिवार रात कहा कि अमेरिका के साथ शांति वार्ता में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन दोनों पक्ष अभी भी समझौते से कोसों दूर हैं। मोहम्मद बाघर ग़ालिबाफ ने राष्ट्रीय संबोधन में कहा, "हम अभी भी अंतिम चर्चा से काफी दूर हैं।" ईरान की सेना शनिवार को घोषणा कर चुकी है, उसने होर्मुज़ स्ट्रेट पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। उसने चेतावनी दी कि जब तक ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक वह इस जलमार्ग से आवाजाही को रोकता रहेगा। ब्रिटिश सेना ने इस दौरान कहा कि दो ईरानी गनबोटों ने जलडमरूमध्य में एक टैंकर पर गोलीबारी की। भारत ने भी पुष्टि की कि ईरान के हमलों में उसके दो जहाजों को निशाना बनाया गया।

मोदी ने सड़क किनारे दुकान पर बच्चों को झालमूड़ी खिलाई

■ चुनाव सभा के बाद हेलीकॉफ्टर की ओर जाते समय मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ झालमूड़ी की दुकान पर काफिला रुकवाया

कोलकाता, 19 अप्रैल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक अलग और सहज अंदाज झाड़ग्राम में देखने को मिला। चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद एसपीजी की भारी सुरक्षा तोड़ प्रोटोकॉल से बाहर निकल कर प्रधानमंत्री मोदी अचानक सड़क किनारे स्थित एक दुकान पर रुक गए। इस दौरान उन्होंने झालमुड़ी (चावल का भुज्जा जो तेल प्याज और मिर्ची मिलाकर बनाया जाता है) का स्वाद लिया, बच्चों और महिलाओं को खिलाया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री के अचानक रुकने से सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर्मी भी कुछ क्षणों के लिए चौंक गए, जबकि स्थानीय लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करने पहुंचे थे। झाड़ग्राम में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रेरा के तहत पंजीकृत नहीं कराने पर न्यू वर्ल्ड जयपुर रिसोर्ट पर 50 लाख की पेनल्टी

प्रोजेक्ट डेवलपर किमाया रिजॉट्स को विला खरीदार के 19.60 लाख ब्याज समेत लौटाने के आदेश भी दिए रेरा ने

■ रेरा ने शिकायतकर्ता अर्जुन सिंह के वकील आतिशे जैन के इस तर्क को स्वीकारा कि किमाया रिजॉर्ट्स दरअसल अलग-अलग यूनिट ही बेच रही थी और उन बेची गई यूनिट्स को "लीज़बैक" (यानी किराए पर वापस लेने) का समझौता कर रही थी, परंतु इस व्यवस्था को अपनाकर वह रेरा कानून के नियमों से बच नहीं सकती है।

■ आतिशे की ओर से कहा गया कि किमाया रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल अपना रही थी, परंतु अलग-अलग यूनिट बेचे जाने की "सेल डीड" में निवेशकों को खरीदार ही बताया गया है और इन "डीड" में स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर्टी बेचने के लिए ही भरी गई है न कि लीज़ करने के लिए।

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुरः रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) राजस्थान, ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि रिसोर्ट और होटल के निर्माणकार्य करने वाला व्यवसाई अगर कोई विला/यूनिट किसी भी खरीदार को शाश्वत पट्टा एकीकरण (पी एल एल ए) समझौता के तहत बेचता है तो उसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को रेरा के अंतर्गत पंजीकृत कराना आवश्यक है। और जिन खरीदारों को यह प्रोजेक्ट्स बेचे गए हैं, उन्हें आवंटी घोषित करना होगा। रेरा ने इस मामले में बिल्डर/डेवलपर किमाया रिजॉर्ट्स पर 50 लाख रुपए की अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाई है, क्योंकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रेरा के अंतर्गत पंजीकृत नहीं कराया। आदेश में आगे कहा गया है कि किमाया रिजॉर्ट्स "न्यू वर्ल्ड जयपुर रिसोर्ट" का पंजीकरण तुरंत कराए।

रेरा के समक्ष दायर एक शिकायत में सामने आया कि किमाया रिजॉर्ट्स एंड स्पा एल एल पी ने अनुज सिंह को "रेवेन्यू शेयरिंग" मॉडल के आधार पर न्यू वर्ल्ड जयपुर रिसॉर्ट प्रोजेक्ट में पूल्ड-सर्विस विला में निवेश करने के लिए अवसर दिया था। अर्जुन सिंह और उनके उत्तराधिकारियों ने दो अलग अलग निवेश, जो दिसंबर 2022 और फरवरी 2023 में किये गए थे, में कुल 19.60 लाख रुपए निवेश किया था। उन्हें किमाया रिजॉर्ट्स की ओर से आश्वासन दिया गया था कि 1 अप्रेल 2023 तक विला का कब्जा दे दिया जाएगा, परन्तु अर्जुन सिंह और उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा इतना बड़ा निवेश करने के बाद भी डेवलपर किमाया रिजॉर्ट्स ने उन्हें न तो जरूरी दस्तावेज भेजे और न ही प्रोजेक्ट का कब्जा दिया। इसके बाद 31 मई 2024 को अर्जुन सिंह के वकील आतिशे जैन ने डेवलपर किमाया रिजॉर्ट्स को पूरी राशि रिफंड करने के संबंध में नोटिस भेजा। परंतु इस नोटिस का कोई भी जवाब नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता को रेरा का दरवाजा खटखटाना ही पड़ा।

सुनवाई के दौरान, किमाया रिजॉर्ट्स की ओर से कहा गया कि यह मामला रेरा के कार्यक्षेत्र के बाहर है, क्योंकि किमाया रिजॉर्ट्स हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में कार्य करते हैं, न कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में। उन्होंने कहा कि उनके प्रोजेक्ट्स में अर्जुन सिंह एक निवेशक थे जो "रेवेन्यू शेयरिंग" मॉडल के आधार पर निवेश करने आए थे। उन्होंने कहा कि अर्जुन सिंह किसी भी सूरत में एक आवंटी नहीं थे, जिन्हें किमाया रिजॉर्ट्स ने कोई मकान या यूनिट बेची थी।

रेरा ने शिकायतकर्ता अर्जुन सिंह के वकील आतिशे जैन के तर्क को स्वीकारा कि किमाया रिजॉर्ट्स दरहसल अलग अलग यूनिट ही बेच रही थी और उन बेची गई यूनिट्स को "लीज़बैक" (यानी किराए पर वापस लेने) का समझौता कर रही थी, परंतु इस व्यवस्था को अपनाकर वह रेरा कानून के नियमों से बच नहीं सकती है। आतिशे की ओर से कहा गया कि किमाया रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल अपना रही थी परंतु अलग अलग यूनिट बेचे जाने की "सेल डीड" में निवेशकों को खरीदार ही बताया गया है और इन "डीड" में स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर्टी बेचने के लिए ही भरी गई है, न कि लीज़ करने के लिए।

रेरा ने सभी तर्कों को सुनने के बाद आदेश दिए कि किमाया रिजॉर्ट्स शिकायतकर्ताओं को 10.8 प्रति वर्ष की दर पर ब्याज लगाकर 19.60 लाख रुपए ब्याज समेत लौटाए । रेरा ने किमाया रिजॉर्ट्स पर 50 लाख रुपए की अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाई है, क्योंकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रेरा के अंतर्गत पंजीकृत नहीं कराया और आदेश दिए कि किमाया रिजॉर्ट्स "न्यू वर्ल्ड जयपुर रिसोर्ट" का पंजीकरण तुरंत कराए।

उत्साहित विपक्ष फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने के मूड में

■ इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टियाँ महाभियोग का संभावित मसौदा तैयार करने में जुट गई बताते हैं।

नई दिल्ली, 19 अप्रैल। लंबी बहस और मतभेदों के बीच शुक्रवार को संविधान का 131वां संशोधन बिल लोकसभा में गिर गया। यह बिल महिला आरक्षण कानून में संशोधन लाने के लिए लाया गया था।

कुल मिलाकर महिला आरक्षण कानून पास नहीं हो पाया। इसे लेकर राजनीतिक घमासान तेज है। संसद में इस जीत से उत्साहित विपक्ष एक और अहम फैसला लेने की तैयारी कर रहा है। विपक्षी दल सीईसी के खिलाफ फिर से महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं।

कांग्रेस एवं टीएमसी समेत, विपक्षी पार्टियां संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)